



44 नोट्स	7 खबरें जोड़ी गईं	GS1 • 7 GS2 • 21 GS3 • 16 पेपर मिश्रण
-------------	----------------------	--

विषय सूची

सभी नोट्स, पेपर के अनुसार

GS1	इतिहास • समाज • भूगोल	7 नोट्स
	इतिहास एवं संस्कृति	3
	भारतीय समाज	4
GS2	राजव्यवस्था • शासन • सामाजिक न्याय • अंतर्राष्ट्रीय संबंध	21 नोट्स
	राजव्यवस्था एवं संविधान	8
	शासन	2
	सामाजिक न्याय	4
	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	7
GS3	अर्थव्यवस्था • विज्ञान-तकनीक • पर्यावरण • सुरक्षा	16 नोट्स
	अर्थव्यवस्था	7
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	6
	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	1
	आंतरिक सुरक्षा	2

हर नोट में

चर्चा में क्यों → याद रखने योग्य तथ्य → कीवर्ड के साथ मेन्स प्रश्न। एक ही खबर की रिपोर्टें जोड़ दी गई हैं।

समय कम है?

5 पेज के सार में सबसे ज़रूरी खबरें और अभ्यास प्रश्न हैं।

इतिहास एवं संस्कृति

3

HERITAGE SITES, UNESCO & GI TAGS

P

M

14 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/104198

ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के धीमे डिजिटाइजेशन पर संसदीय समिति ने जताई चिंता

चर्चा में क्यों परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लक्ष्य में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त की है।

योजना	ज्ञान भारतम मिशन: सांस्कृतिक संरक्षण के लिए पांडुलिपियों को डिजिटल बनानेकी एक सरकारी पहल।
तथ्य	लक्ष्य: 2030 तक 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण।
तथ्य	वर्तमान प्रगति: अगस्त 2026 तक 7.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

मेन्स प्रश्न भारत के इतिहास के संरक्षण में सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण के महत्व और बड़े पैमाने पर पांडुलिपि संरक्षण परियोजनाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

MODERN INDIA & FREEDOM STRUGGLE

P

14 अगस्त · The Hindu · satyadheesh.in/news/103978

मद्रास उच्च न्यायालय प्रशासन ने राष्ट्रीय गान से पूर्व 15 अगस्त, 2026 को 'वन्दे मातरम्' बजाने की घोषणा की है

चर्चा में क्यों मद्रास उच्च न्यायालय प्रशासन ने राष्ट्रीय गान से पूर्व 15 अगस्त, 2026 को 'वन्दे मातरम्' बजाने की घोषणा की है, ताकि राष्ट्रीय गान की 150वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया जा सके।

तथ्य	Vande Mataram की 150वीं वर्षगांठ 2026 में मनाई जाएगी।
स्थान	यह पहल तमिलनाडु और Puducherry की न्यायिक इकाइयों को कवर करती है।
संस्था	उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल न्यायालय के प्रशासनिक निर्णयों की देखरेख करते हैं।

मेन्स प्रश्न भारत के विविध नागरिकों के बीच राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय प्रतीकों और गीतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

HERITAGE SITES, UNESCO & GI TAGS

P

M

14 अगस्त · NDTV · satyadheesh.in/news/103641

18 ऐतिहासिक साइट्स लिस्ट से बाहर, राष्ट्रीय महत्व के मानदंडों पर खरी नहीं पाई गई

चर्चा में क्यों केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने राष्ट्रीय महत्व के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने के कारण संरक्षित स्मारकों की सूची से 18 ऐतिहासिक स्थलों को हटाने की घोषणा की है।

संस्था	ASI: Archaeological Survey of India भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है।
अधिनियम	प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958: पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
तथ्य	3,688: ASI द्वारा संरक्षित वर्तमान केंद्रीय संरक्षित स्थलों की संख्या।
अधिनियम	Public Records Act, 1993: यह सार्वजनिक अभिलेखों के संरक्षण और ऑडिटिंग को नियंत्रित करता है।

मेन्स प्रश्न भारत में शहरी विकास और विरासत स्थलों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) राष्ट्रीय विरासत की अखंडता को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? चर्चा कीजिए।

2027 की जनसंख्या जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना

चर्चा में क्यों जनगणना 2027 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत में पहली डिजिटल और जाति-आधारित जनगणना होगी।

- तथ्य | जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
- तथ्य | Housing Listing Operations (HLO) का समापन 30 सितंबर, 2026 को हुआ।
- तथ्य | जनगणना के लिए स्व-गणना (Self-enumeration) 17 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध है।

मेन्स प्रश्न भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाने में डिजिटल जनगणना गणना और जातिगत डेटा के समावेश के महत्व पर चर्चा कीजिए।

भारत रजिस्ट्रार ने बर्फबारी वाले इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होने वाली जनगणना के लिए 40 सवाल अधिसूचित किए

चर्चा में क्यों भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने आगामी जनसंख्या गणना के लिए 40 जनगणना प्रश्नों को अधिसूचित किया है, जिसमें विशेष रूप से पहली बार स्व-रिपोर्टिंग के माध्यम से जाति का विवरण शामिल किया गया है।

- तथ्य | जनगणना के लिए आवंटित कुल बजट: Rs 11,718 करोड़।
- तथ्य | स्व-गणना अवधि: 17 अगस्त से 31 अगस्त।
- संस्था | भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India): भारत में जनगणना आयोजित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण।
- तथ्य | पहली बार स्व-रिपोर्टिंग के आधार पर जाति का विवरण एकत्र किया जाएगा।

मेन्स प्रश्न सामाजिक-आर्थिक नीतियां तैयार करने में जनगणना के महत्व और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

अरुणाचल प्रदेश ने 80:20 आरक्षण खत्म किया, स्थानीय भाषा में दक्षता अनिवार्य

चर्चा में क्यों अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए 80:20 आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर स्वदेशी भाषा में दक्षता सहित समान पात्रता मानदंड लागू किए हैं।

- संस्था | APPSC: Arunachal Pradesh Public Service Commission राज्य सिविल सेवाओं के लिए उत्तरदायी निकाय है।
- तथ्य | पिछली आरक्षण प्रणाली में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए 80:20 का अनुपात अपनाया गया था।
- स्थान | अरुणाचल प्रदेश: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य।

मेन्स प्रश्न सांस्कृतिक रूप से विविध राज्यों में सार्वजनिक सेवा भर्ती की समावेशिता पर भाषाई दक्षता और निवास संबंधी आवश्यकताओं के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

DDA ने मास्टर प्लान 2047 को दी मंजूरी, केंद्र की मंजूरी का इंतज़ार

चर्चा में क्यों दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने वर्ष 2047 तक 40 लाख आवास इकाइयों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से 'मास्टर प्लान 2047' को स्वीकृति प्रदान की है, जो वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुमोदन हेतु लंबित है।

- संस्था | DDA: Delhi Development Authority दिल्ली में भूमि और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- तथ्य | Master Plan 2047 के अनुसार, 2047 तक 40 लाख अतिरिक्त घरों की आवश्यकता का लक्ष्य रखा गया है।
- तथ्य | प्रस्तावित छोटे घरों का कालीन क्षेत्र (carpet area) 25 से 60 वर्ग मीटर के बीच है।
- संस्था | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय: दिल्ली मास्टर प्लान की अंतिम स्वीकृति के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय।

मेन्स प्रश्न दिल्ली जैसे तेजी से बढ़ते महानगरीय शहरों में शहरी आवास की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन समस्याओं के समाधान में 'परिवहन-उन्मुख विकास' (Transit-Oriented Development) और 'भूमि पूलिंग' (Land Pooling) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

राज्यव्यवस्था एवं संविधान

8

FUNDAMENTAL RIGHTS, DPSP & DUTIES

P

M

14 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/103786

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: भारत में हर गिरफ्तारी के लिए सीधा कम्युनिकेशन जरूरी

चर्चा में क्यों विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह निर्णय दिया कि सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की प्रत्यक्ष सूचना देना अनिवार्य है।

संविधान	अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्राप्त करने और कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार की गारंटी देता है।
अधिनियम	Code of Criminal Procedure (CrPC) की धारा 50 व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करना अनिवार्य बनाती है।
पद	उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।

मेन्स प्रश्न राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में गिरफ्तारी के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

FUNDAMENTAL RIGHTS, DPSP & DUTIES

P

M

14 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/103532

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा सांसद ए.ए. रहीम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की

चर्चा में क्यों उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा सांसद ए.ए. रहीम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध फेशियल रिक्निशन टेक्नोलॉजी और व्यापक निगरानी (mass surveillance) के उपयोग को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है।

विज्ञान	Facial Recognition Technology (FRT) वास्तविक समय (real-time) में या संग्रहीत छवियों से व्यक्तियों की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करती है।
संस्था	भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास उन कार्यकारी कार्यों को रद्द करने की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
तथ्य	यह याचिका सरकार द्वारा एकत्रित किए गए बायोमेट्रिक डेटा की मेजबानी (hosting) में निजी एजेंसियों की संलिप्तता को रेखांकित करती है।

मेन्स प्रश्न एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली निगरानी और निजता के मौलिक अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोध का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

M

2 रिपोर्टें जोड़ी गईं

14 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/104150

करूर भगदड़ पीड़ितों के जॉब ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, गांधी हेट स्पीच केस रद्द

चर्चा में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ की पीड़ितों के लिए सरकारी नौकरियों से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने हेतु हस्तक्षेप किया और एक घृणास्पद भाषण (hate speech) के मामले को रद्द कर दिया, जो कार्यकारी कार्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है।

संस्था	भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है।
तथ्य	उच्चतम न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने की शक्ति है।
स्थान	करूर: तमिलनाडु राज्य का एक शहर।
संस्था	White House: यह US राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है।

मेन्स प्रश्न सामाजिक कल्याण प्रदान करने के लिए कार्यपालिका की शक्तियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

हरियाणा में electoral rolls का विशेष गहन पुनरीक्षण समस्या पैदा कर रहा है

चर्चा में क्यों हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के कारण अन्य राज्यों से विवाह कर यहाँ आई महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुरानी मतदाता सूचियों में उनके अभिभावकीय रिकॉर्ड का अभाव है।

तथ्य | वर्तमान संशोधन प्रक्रिया सत्यापन के लिए 2002 की मतदाता सूची को आधार मानती है।

संस्था | निर्वाचक नामा (Electoral Rolls) भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा संधारित किए जाते हैं।

मेन्स प्रश्न निर्वाचक नामा संशोधन की प्रक्रिया में हाशिए पर रहने वाले समूहों और प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और समावेशी मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने BCI को NALSAR ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट पर बैन हटाने का आदेश दिया

चर्चा में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR स्नातकों के नामांकन को रोकने से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को प्रतिबंधित करने के लिए हस्तक्षेप किया, जो नियामक निकायों की दंडात्मक शक्तियों की सीमाओं को रेखांकित करता है।

संस्था | Bar Council of India (BCI): भारत में कानूनी अभ्यास और शिक्षा के मानकों को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था।

स्थान | NALSAR University of Law: यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है।

तथ्य | BCI का निर्देश विशेष रूप से NALSAR के 2026 के स्नातक होने वाले बैच को लक्षित करता है।

मेन्स प्रश्न पेशेवर मानकों को विनियमित करने में वैधानिक निकायों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि वे छात्रों और पेशेवरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।

हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल की बरी होने पर फैसला पलटा, क्रॉस-एग्जामिनेशन को बताया "Invasive"

चर्चा में क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दी गई दोषमुक्ति की सजा को पलट दिया है, जिसमें कानूनी निषेधों के बावजूद बलात्कार पीड़ितों की 'आक्रामक' जिरह (cross-examination) के मुद्दे को रेखांकित किया गया है।

अधिनियम | भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A यौन अपराधों के पीड़ित के पिछले यौन अनुभव के संबंध में प्रश्नों को प्रतिबंधित करती है।

संविधान | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है।

तथ्य | बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के एक बलात्कार और हमले के मामले में तरुण तेजपाल की दोषमुक्ति (acquittal) को पलट दिया।

मेन्स प्रश्न यौन अपराधों के मामलों में आक्रामक प्रति-परीक्षण (cross-examination) के विरुद्ध मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, पीड़ित-केंद्रित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

CJI सूर्यकांत ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका पर दिया जोर

चर्चा में क्यों मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका और हाशिए पर रहने वाले समूहों की सुरक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता के उपयोग पर बल दिया।

पद | CJI सूर्यकांत: नवंबर 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश।

विज्ञान | PIL: Public Interest Litigation किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मामला दायर करने की अनुमति देता है।

तथ्य | न्यायिक सक्रियता (Judicial activism) में 'suo motu' कार्यवाई शामिल है, जहाँ न्यायालय स्वयं की पहल पर किसी मामले को लेता है।

मेन्स प्रश्न भारत में संविधान के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के अधिकारों के संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

चिंदंबरम की कानूनी चुनौती के बीच संघ लोक सेवा आयोग ने DG Police के चयन में देरी की

चर्चा में क्यों प्रकाश सिंह निर्णय के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित एक कानूनी चुनौती के कारण, UPSC ने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन प्रक्रिया में विलंब किया है।

संस्था	UPSC: अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो All India Services और Central Services के लिए नियुक्तियाँ करता है।
तथ्य	प्रकाश सिंह मामला: पुलिस सुधार और योग्यता-आधारित भर्ती के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय (2006)।
पद	पुलिस महानिदेशक (DGP): किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी, जिन्हें सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मेन्स प्रश्न पुलिस भर्ती प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में प्रकाश सिंह निर्णय के महत्व और संस्थागत स्वायत्तता बनाए रखने में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

शासन

2

कर्नाटक ने सार्वजनिक संपत्ति पर इवेंट्स के लिए परमिशन की मांग वाला बिल पेश किया

चर्चा में क्यों कर्नाटक सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्वजनिक संपत्ति के अनधिकृत उपयोग को रोकने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के लिए इसके उपयोग को विनियमित करने हेतु एक विधेयक प्रस्तावित किया है।

अधि नियम	कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल, 2026।
तथ्य	आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम सात दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
तथ्य	पुनरावृत्ति वाले अपराधों के लिए दंड में 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

मेन्स प्रश्न सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के उपयोग को विनियमित करने में विधायी ढाँचों के महत्व पर चर्चा कीजिए, ताकि व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। चर्चा कीजिए।

कर्नाटक में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किए नए पार्किंग रूल्स

चर्चा में क्यों कर्नाटक शहरी विकास विभाग ने शहर की सशुल्क पार्किंग प्रणाली में व्यापक सुधार करने और नगरपालिका राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से 'ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (पार्किंग) नियम, 2026' प्रकाशित किए हैं।

संस्था	DULT: Directorate of Urban Land Transport कर्नाटक में शहरी परिवहन नियोजन के लिए जिम्मेदार निकाय है।
तथ्य	नए नियमों का उद्देश्य मौजूदा सशुल्क पार्किंग प्रणाली में कम मांग और कार्यान्वयन संबंधी संघर्षों को संबोधित करना है।
स्थान	ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी: नए पार्किंग नियमों के लिए विशिष्ट अधिकार क्षेत्र।

मेन्स प्रश्न तेजी से बढ़ते भारतीय शहरों में कुशल शहरी पार्किंग प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।

सामाजिक न्याय

4

केरल ने केयरगिवर सहायता ₹600 से बढ़ाकर ₹1,000 की की

चर्चा में क्यों केरल सरकार ने वृद्धों या दिव्यांगों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों की सहायता हेतु 'अश्वासकिरण' (Ashwasakiranam) योजना के अंतर्गत मासिक देखभाल सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया है।

योजना	अश्वासकिरणम: केरल राज्य सरकार की एक योजना जो देखभाल करने वालों (caregivers) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
तथ्य	2026-27 के बजट में मासिक केयरगिवर सहायता को ₹600 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है।
संस्था	केरल सोशल सिक्योरिटी मिशन: राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय।

मेन्स प्रश्न भारत के वृद्ध होती जनसंख्या वाले समाज में बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहायता करने में राज्य-संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।

आंध्र मंत्री: राज्य की लगभग आधी आबादी ओवरवेट, जॉइंट टास्क फोर्स की योजना

चर्चा में क्यों आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मोटापे से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य बल (joint task force) की घोषणा की है, क्योंकि NFHS-6 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की लगभग आधी आबादी इससे प्रभावित है।

तथ्य	NFHS-6: National Family Health Survey के आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश की लगभग 50% जनसंख्या ओवरवेट (overweight) है।
योजना	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK): बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की स्क्रीनिंग और प्रबंधन के लिए एक सरकारी पहल।
संस्था	खाद्य सुरक्षा विभाग: खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय।

मेन्स प्रश्न भारत में मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की बढ़ती चुनौती पर चर्चा कीजिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान हेतु एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का सुझाव दीजिए।

फ्रंट-ऑफ-पैक वार्निंग लेबल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को फटकारा

चर्चा में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक' चेतावनी लेबल लागू करने में देरी के लिए FSSAI की आलोचना की।

संस्था	FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए सर्वोच्च निकाय।
तथ्य	उच्चतम न्यायालय की सुनवाई 13 अगस्त, 2026 को हुई।
पद	न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने नियामक देरी की आलोचना करने वाली पीठ की अध्यक्षता की।

मेन्स प्रश्न जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने में अनिवार्य लेबलिंग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ वर्कर्स के लिए Samasta डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने का आदेश दिया

चर्चा में क्यों कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ASHA और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए डेटा संग्रहण को सुव्यवस्थित करने हेतु 'Samasta' डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है।

संस्था	ASHA (Accredited Social Health Activist) कार्यकर्ता भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं।
तथ्य	Samasta प्लेटफॉर्म सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्षमताओं का समर्थन करता है।
स्थान	इस प्लेटफॉर्म का प्रथम परीक्षण कर्नाटक के उडुपी जिले में किया गया था।

मेन्स प्रश्न भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण की दक्षता और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका को बढ़ाने में 'समस्ता' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के एकीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

7

यू.एस. रिपोर्ट में पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को 'Great Transshipment Scam' में नामजद किया

चर्चा में क्यों व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को चीन द्वारा अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अवैध पारगमन (transshipment) के एक केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

तथ्य	अनिवार्य श्रम (forced labor) के आयात को रोकने में विफल रहने पर यू.एस. ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया है।
स्थान	पुणे-गुजरात-चेन्नई बेल्ट को विशेष रूप से एक ट्रांसशिपमेंट हब (transshipment hub) के रूप में पहचाना गया था।
तथ्य	यह रिपोर्ट अवैध ट्रांसशिपमेंट (transshipment) जोखिम से जुड़े 40 से अधिक देशों की पहचान करती है।

मेन्स प्रश्न व्यापार संबंधी आरोपों और टैरिफ (शुल्क) अधिरोपण का भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

बांग्लादेश के PM Tarique Rahman द्विपक्षीय talks के लिए भारत आएंगे

चर्चा में क्यों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, तनावपूर्ण संबंधों को पुनर्जीवित करने और रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से द्विपक्षीय वार्ता हेतु भारत के दौरे पर जाने वाले हैं।

स्थान	अगतला-अखौरा रेल-लिंक: यह उत्तर-पूर्वी भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है।
तथ्य	भारत ने 2009-2019 के बीच बांग्लादेश को \$8 बिलियन की Lines of Credit प्रदान कीं।
पद	दिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त।
संस्था	BRICS: एक बहुराष्ट्रीय मंच जहाँ ढाका ने बहुपक्षीय संवाद के बजाय द्विपक्षीय बैठक को प्राथमिकता दी।

मेन्स प्रश्न बांग्लादेश के साथ भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को सुदृढ़ करने में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Turkey, Pakistan और Saudi Arabia ने NATO के Article 5 की तर्ज पर डिफेंस समझौता किया

चर्चा में क्यों तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, जो NATO के अनुच्छेद 5 के समान है।

अंतः संगठन	NATO Article 5: एक सामूहिक रक्षा खंड जो यह निर्धारित करता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है।
तथ्य	नए समझौते के हस्ताक्षरकर्ता: Turkey, Pakistan और Saudi Arabia।
विज्ञान	यह समझौता तकनीकी और सैन्य प्रगति के लिए रक्षा उद्योग में सहयोग पर बल देता है।

मेन्स प्रश्न पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में उभरते त्रिपक्षीय रक्षा समझौतों के क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत ने "आतंकवाद को पनाह देने वाले" पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित की

चर्चा में क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के कारण पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करने की घोषणा की।

अंतः संगठन	सिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल-साझाकरण संधि।
तथ्य	ऑपरेशन सिंदूर: आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उद्धृत एक सैन्य अभियान।
पद	राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: भारत की वर्तमान राष्ट्रपति।

मेन्स प्रश्न सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा: Pew सर्वे में 54% लोगों ने पड़ोसी देश पर जताया अविश्वास

चर्चा में क्यों प्यू रिसर्च (Pew Research) के एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि 54% भारतीय वयस्क पाकिस्तान को अपना प्राथमिक भू-राजनीतिक खतरा मानते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर गहरे अविश्वास को रेखांकित करता है।

रिपोर्ट	Pew Research: वैश्विक जनमत सर्वेक्षण आयोजित करने वाला अमेरिकी थिंक टैंक।
तथ्य	सर्वेक्षण में शामिल 54% भारतीय वयस्क पाकिस्तान को सबसे बड़ा भू-राजनीतिक खतरा मानते हैं।
तथ्य	सर्वेक्षण में शामिल 21% भारतीय वयस्कों ने चीन को एक भू-राजनीतिक खतरे (geopolitical threat) के रूप में पहचाना है।

मेन्स प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी पैठी आपसी अविश्वास किस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग में बाधा उत्पन्न करता है और भारत की सुरक्षा संरचना को कैसे प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

2025 में भारतीयों पर विदेशों में हमले बढ़कर 104 हुए, ज्यादातर US, UAE, UK और Canada में

चर्चा में क्यों विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय नागरिकों पर होने वाले हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है, जो भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करता है।

तथ्य	2021 और 2025 के बीच विदेशों में भारतीयों पर हुए हमलों के कुल दर्ज मामले 302 तक पहुँच गए।
तथ्य	वर्ष 2025 में अधिकांश घटनाओं के लिए US, UAE, UK और Canada जिम्मेदार थे।
पद	कीर्ति वर्धन सिंह राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय हैं।

मेन्स प्रश्न भारतीय प्रवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमा पार होने वाले अपराधों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

ट्रंप प्रशासन ने भारत और कनाडा समेत 40 से ज्यादा देशों को फ्लैग किया

चर्चा में क्यों ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित 40 से अधिक देशों को कथित तौर पर ट्रांसशिपमेंट योजनाओं के माध्यम से चीनी टैरिफ चोरी (tariff evasion) की सुविधा प्रदान करने के लिए चिह्नित किया है।

तथ्य	Section 301 tariffs: अमेरिकी व्यापार कानून का उपयोग विदेशी देशों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए किया जाता है।
विज्ञान	ट्रंप प्रशासन ट्रांसशिपमेंट पैटर्न का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए Artificial Intelligence (AI) को तैनात करने की योजना बना रहा है।
तथ्य	यह रिपोर्ट भारत, कनाडा और EU सहित 40 से अधिक देशों को इन प्रथाओं के सुगमकर्ता के रूप में पहचानती है।

मेन्स प्रश्न वैश्विक व्यापार की गतिशीलता पर पारगमन (transshipment) और शुल्क चोरी (tariff evasion) द्वारा उत्पन्न चुनौतियों तथा व्यापार पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

अर्थव्यवस्था

7

FISCAL POLICY, BUDGET & TAXATION (GST)

P

M

14 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/103926

बिल से राज्यों की मिनरल टैक्स पावर खत्म, 11 प्रभावित क्षेत्र फिस्कल लिम्बो में

चर्चा में क्यों लोकसभा ने खनिज और खनिज पदार्थ (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जो खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, जिससे संघीय राजकोषीय स्वायत्तता प्रभावित होती है।

अधिनियम	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
तथ्य	यह विधेयक झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों को प्रभावित करता है।
तथ्य	यह विधेयक 2005 से संबंधित खनिज कर बकाया (mineral tax arrears) को शून्य कर देता है।

मेन्स प्रश्न खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संघवाद तथा राजस्व-साझाकरण की गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

MONETARY POLICY, RBI & BANKING

P

M

14 अगस्त • Economic Times • satyadheesh.in/news/104176

SEBI ने OBPPs को RBI, IRDAI, IFSCA और PFRDA द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करने की अनुमति दी

चर्चा में क्यों SEBI ने पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म (OBPPs) के दायरे का विस्तार किया है, ताकि वे विभिन्न वित्तीय निकायों द्वारा विनियमित उत्पादों की पेशकश कर सकें।

संस्था	SEBI: Securities and Exchange Board of India, प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करता है।
संस्था	IRDAI: Insurance Regulatory and Development Authority of India।
संस्था	IFSCA: International Financial Services Centres Authority।
संस्था	PFRDA: Pension Fund Regulatory and Development Authority।
तथ्य	कर कानूनों के धारा 54EC और 85 कर-बचत वाले बॉन्ड और पूंजीगत लाभ (capital gains) से संबंधित हैं।

मेन्स प्रश्न ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म (OBPPs) के विस्तार से भारतीय ऋण बाजार में खुदरा भागीदारी को कैसे बढ़ावा मिल सकता है और इसमें निहित विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

EMPLOYMENT & INCLUSIVE GROWTH

P

M

14 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/104169

युवा बेरोजगारी बढ़कर 16.2% हुई, युवा महिलाओं के लिए नौकरी ढूंढना 20.7% मुश्किल

चर्चा में क्यों आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ने युवा बेरोजगारी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो श्रम बाजार में बढ़ते लैंगिक और नगरीय-ग्रामीण अंतर को रेखांकित करता है।

तथ्य	जून 2026 में भारत में युवा बेरोजगारी दर 16.2% तक पहुंच गई।
तथ्य	शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर (18.2%) ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दर (15.1%) से अधिक है।
तथ्य	महिला युवा बेरोजगारी (20.7%) की दर, पुरुष युवा बेरोजगारी (14.6%) की तुलना में काफी अधिक है।
संस्था	Periodic Labour Force Survey (PLFS) भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है।

मेन्स प्रश्न भारत में युवा बेरोजगारी में बढ़ते लैंगिक और शहरी-ग्रामीण अंतराल में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और समावेशी रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए उचित उपाय सुझाइए।

निवेशकों के लिए रेटिंग आसान बनाने हेतु Sebi ने 6 कलर कोड वाला Credit Risk-o-Meter प्रस्तावित किया

चर्चा में क्यों निवेशक संरक्षण को सुदृढ़ करने उद्देश्य से SEBI ने ऋण प्रतिभूतियों (debt securities) की जटिल क्रेडिट रेटिंग्स को सरल बनाने के लिए 'Credit Risk-o-Meter' का प्रस्ताव दिया है।

संस्था	SEBI: भारत में प्रतिभूति (securities) और कमोडिटी बाजारों को विनियमित करने वाली एक वैधानिक संस्था।
तथ्य	प्रस्तावित Credit Risk-o-Meter जोखिम के स्तरों को दर्शाने के लिए छह अलग-अलग रंग कोडों का उपयोग करता है।
तथ्य	SEBI ने 3 सितंबर तक प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियों की मांग की है।

मेन्स प्रश्न भारतीय ऋण बाजार में क्रेडिट रेटिंग प्रकटीकरण को सरल बनाने से निवेशक सुरक्षा और पारदर्शिता को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।

SEBI ने विदेशी क्लाइंट्स के लिए वीडियो-आधारित KYC का प्रस्ताव दिया, पब्लिक कमेंट्स मांगे

चर्चा में क्यों SEBI ने नियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विदेशी ग्राहकों (PROI) के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक वीडियो-आधारित KYC ढांचे का प्रस्ताव दिया है।

संस्था	SEBI: भारत में प्रतिभूति (securities) और कमोडिटी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
तथ्य	PROI: इसमें Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizens of India (OCIs) और विदेशी नागरिक शामिल हैं।
संस्था	FATF: Financial Action Task Force, एक अंतर-सरकारी निकाय है जो धन शोधन (money laundering) को रोकने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है।
विज्ञान	Video-based KYC: पहचान सत्यापित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए लाइव वीडियो का उपयोग करने वाली एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया।

मेन्स प्रश्न वीडियो-आधारित पहचान जैसे डिजिटल केवाईसी (KYC) ढाँचों को अपनाने से वित्तीय समावेशन की आवश्यकता और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने की अनिवार्यता के बीच संतुलन कैसे स्थापित होता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

India ने MCX पर Crude Sunflower Oil futures contract लॉन्च किया

चर्चा में क्यों MCX ने एक ऐसे वस्तु के लिए कच्चे सूरजमुखी तेल का वायदा अनुबंध (futures contract) शुरू किया है, जिसके लिए भारत भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है, ताकि इसकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम किया जा सके।

संस्था	MCX: Multi Commodity Exchange of India एक प्रमुख कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है।
तथ्य	भारत अपनी वार्षिक खाद्य तेल आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है।
तथ्य	भारत के कुल खाद्य तेल उपभोग में सूरजमुखी तेल की हिस्सेदारी लगभग 9% है।
तथ्य	नया Crude Sunflower Oil फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट Ex-Tank JNPT कीमतों के आधार पर कैश-सेटल किया जाता है।

मेन्स प्रश्न भारत के खाद्य तेल क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में वस्तु डेरिवेटिव बाजारों के विकास किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

SAT ने SEBI के फैसले को पलटा: Zee Entertainment को Rs 3,143 करोड़ के इश्यू की मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों सिक्योरिटीज अपील न्यायाधिकरण (SAT) ने Zee Entertainment के विरुद्ध SEBI के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन के आरोपों के बावजूद ₹3,143 करोड़ के प्रेफरेंशियल वारंट जारी करने की अनुमति मिल गई है।

संस्था	SAT (Securities Appellate Tribunal) प्रतिभूति बाजार विवादों के लिए पहला अपीलीय न्यायाधिकरण है।
संस्था	SEBI (Securities and Exchange Board of India) भारतीय प्रतिभूति बाजार का प्राथमिक नियामक है।
तथ्य	Zee Entertainment को ₹3,143 करोड़ के प्रेफरेंशियल वारंट इश्यू (preferential warrant issue) के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई।
तथ्य	यह विवाद हैदराबाद की एक संपत्ति से संबंधित कथित धोखाधड़ी वाले शीर्षक विलेख (title deed) लेनदेन से संबंधित है।

मेन्स प्रश्न सेबी (SEBI) द्वारा कड़े बाजार विनियमन और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए व्यापार सुगमता (ease of doing business) के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

DEFENCE TECHNOLOGY

P

M

14 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/104099

DRDO को 2026 तक AI में मुकाबला करने और सुव्यवस्थित होने के लिए PMO से मिले सुधारों पर काम करना होगा

चर्चा में क्यों PMO ने 2026 तक AI और स्वायत्त प्रणालियों (autonomous systems) में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए सुधारों के निर्देश दिए हैं।

संस्था	DRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की प्राथमिक R&D इकाई।
विज्ञान	DRDO सुधारों के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में AI, semiconductors और autonomous systems शामिल हैं।
तथ्य	इन संरचनात्मक सुधारों को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2026 है।

मेन्स प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

SPACE TECHNOLOGY (ISRO, MISSIONS)

P

14 अगस्त • BBC • satyadheesh.in/news/103714

मैग्नेटिक स्नैप्स ने कोरोना की 93% हीट को पावर देकर एनर्जी लॉस मिस्ट्री को खत्म किया

चर्चा में क्यों भारत के आदित्य-L1 मिशन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए खगोल भौतिकविदों (Astrophysicists) ने यह खोज की है कि चुंबकीय स्नैप्स (magnetic snaps) सौर कोरोना की 93% ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊर्जा हानि से संबंधित एक दीर्घकालिक रहस्य का समाधान हो गया है।

विज्ञान	Aditya-L1: सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला।
तथ्य	मैग्नेटिक स्नैप्स और रिकनेक्शन सौर कोरोना की 93% ऊष्मा के लिए उत्तरदायी हैं।
विज्ञान	सौर कोरोना: सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, जो सतह की तुलना में लाखों डिग्री अधिक गर्म रहती है।

मेन्स प्रश्न सौर भौतिकी के क्षेत्र में प्रगति के संदर्भ में भारत के आदित्य-एल1 (Aditya-L1) मिशन के महत्व और अंतरिक्ष मौसम (space weather) को समझने तथा पृथ्वी पर इसके प्रभावों के विश्लेषण पर चर्चा कीजिए।

DEFENCE TECHNOLOGY

P

14 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/104172

रक्षा मंत्रालय ने तोपखाने की सटीकता बढ़ाने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी फर्मों के साथ 'लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम' (Loiter Munition Systems) के लिए ₹1,577 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं

चर्चा में क्यों रक्षा मंत्रालय ने तोपखाने की सटीकता बढ़ाने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी फर्मों के साथ 'लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम' (Loiter Munition Systems) के लिए ₹1,577 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

विज्ञान	Loiter Munition Systems: स्वायत्त ड्रोन (Autonomous drones) जिन्हें लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडराने और फिर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तथ्य	अनुबंध मूल्य: लगभग Rs 1,577 करोड़।
संस्था	Tata Advanced Systems Limited और NIBE Private Limited वे निजी संस्थाएं हैं जिन्हें गोला-बारूद के लिए अनुबंध दिया गया है।
तथ्य	खरीद श्रेणी: 'Buy (Indian)' श्रेणी का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देना है।

मेन्स प्रश्न रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों की प्राप्ति में 'बाय (इंडियन)' नीति के महत्व पर चर्चा कीजिए।

SPACE TECHNOLOGY (ISRO, MISSIONS)

P

14 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/104091

भारत के 80वें Independence Day पर रूसी कॉस्मोनेट्स Pyotr Dubrov, Anna Kikina

चर्चा में क्यों भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर भारतीय ध्वज फहराया, जो भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक अंतरिक्ष सहयोग को रेखांकित करता है।

विज्ञान	आर्यभट: 1975 में प्रक्षेपित भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह।
विज्ञान	Gaganyaan: भारत का आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
संस्था	ISS: International Space Station, एक सहयोगात्मक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन।
तथ्य	भारत का 80वाँ स्वतंत्रता दिवस 1947-2027 के मील के पत्थर को चिह्नित करता है।

मेन्स प्रश्न भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग के महत्व और गगनयान मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पेलोड लॉन्च के लिए भारत खर्च कर रहा है \$13,302 प्रति Kg, प्रमुख स्पेस देशों में सबसे ज्यादा

चर्चा में क्यों 'इकोनॉमिक्स लेटर्स' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, लघु रॉकेट प्रक्षेपणों की व्यापकता के कारण प्रमुख अंतरिक्ष देशों की तुलना में भारत की प्रति किलोग्राम अंतरिक्ष प्रक्षेपण लागत सर्वाधिक है।

तथ्य	भारत की प्रति किलोग्राम प्रक्षेपण लागत: \$13,302।
तथ्य	यू.एस. लॉन्च लागत प्रति किग्रा: \$3,225।
विज्ञान	ISRO: अंतरिक्ष एजेंसी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग के अधीन।
तथ्य	Economics Letters: वह जर्नल जिसने 14 अगस्त, 2026 को विश्लेषण प्रकाशित किया।

मेन्स प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा प्रक्षेपण लागत को अनुकूलित करने में आने वाली आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और लागत-प्रभावी अंतरिक्ष अन्वेषण प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

जर्मनी ने दुनिया के पहले लकड़ी के विंड टरबाइन ब्लेड लॉन्च किए, CO2 में 78% की कमी

चर्चा में क्यों जर्मनी की 'वूडिन ब्लेड टेक्नोलॉजी' (Woodin Blade Technology) ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से लैमिनेटेड वेनियर लम्बर (LVL) से निर्मित पवन टरबाइन ब्लेड का विश्व का प्रथम प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है।

विज्ञान	Laminated Veneer Lumber (LVL) का उपयोग अधिक पुनर्चक्रण योग्य (recyclable) और टिकाऊ विंड टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए किया जाता है।
तथ्य	लकड़ी के विंड टरबाइन ब्लेड कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 78% तक कम कर सकते हैं।
तथ्य	प्रोटोटाइप ब्लेड की लंबाई 19.3 मीटर है।

मेन्स प्रश्न नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में टिकाऊ सामग्रियों की ओर बढ़ता रुझान भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दे सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

1

जलवायु परिवर्तन नहीं, मानवीय गलतियों से असम में बाढ़, 103 की मौत

चर्चा में क्यों वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (WWA) के एक अध्ययन में यह रेखांकित किया गया है कि पूर्वी असम में आई विनाशकारी बाढ़ का प्राथमिक कारण जलवायु परिवर्तन के बजाय भूमि-उपयोग में परिवर्तन था।

संस्था	World Weather Attribution (WWA) एक वैश्विक पहल है जो चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों की जांच करती है।
स्थान	शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट असम राज्य के जिले हैं।
तथ्य	पूर्वी असम में आई बाढ़ के कारण कम से कम 103 लोगों की मृत्यु हुई।

मेन्स प्रश्न मानवीय भू-उपयोग परिवर्तनों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को किस प्रकार गंभीर बनाया है? सतत बाढ़ प्रबंधन हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

TERRORISM & INSURGENCY (J&K, NORTH-EAST)

P

M

14 अगस्त • NDTV • satyadheesh.in/news/104049

Lashkar-e-Taiba की धमकी के बाद कश्मीरी पंडित वर्कर्स को छुट्टी पर भेजा, पुलिस जांच में जुटी

चर्चा में क्यों अल्पसंख्यक श्रमिकों को लक्षित करते हुए लश्कर-ए-तैबा (LeT) से जुड़े एक धमकी पत्र के बाद, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अवकाश पर भेज दिया गया और उन्हें जम्मू स्थानांतरित कर दिया गया।

तथ्य | Lashkar-e-Taiba (LeT) पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है।

स्थान | जम्मू और कश्मीर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक चिंता का क्षेत्र है।

तथ्य | प्रधानमंत्री का विशेष रोजगार पैकेज (Prime Minister's Special Employment Package) कश्मीरी पंडितों के रोजगार के लिए एक योजना है।

मेन्स प्रश्न संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और लक्षित आतंकवाद को कम करने में राज्य की सुरक्षा तंत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

SECURITY FORCES & AGENCIES

P

14 अगस्त • The Hindu • satyadheesh.in/news/103713

Independence Day पर 1,057 कर्मियों को मिले मेडल, जिनमें 301 Gallantry Medals शामिल

चर्चा में क्यों गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की है।

संस्था | गृह मंत्रालय (MHA) भारत में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस बलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

तथ्य | कुल 301 वीरता पदक (Gallantry Medals) प्रदान किए गए, जिनमें से 272 विशेष रूप से पुलिस कर्मियों को दिए गए।

तथ्य | पुलिस, फायर, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के कर्मियों को पदक प्रदान किए गए।

मेन्स प्रश्न आंतरिक सुरक्षा बलों के बीच वीरता और सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने की राष्ट्रीय अखंडता और जन-मनोबल को बनाए रखने में महत्ता का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + विडिओ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।